भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.-1473
उत्तर देने की तारीख-09.02.2026

तमिलनाडु में पीएम-उषा का कार्यान्वयन

†1473. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के कार्यान्वयन और परिणामों की, विशेषकर सरकारी और सहायताप्राप्त कॉलेजों में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में, समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) राज्य के कितने संस्थानों को पीएम-उषा के तहत सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है और विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पीएम-उषा के हस्तक्षेपों के बावजूद संकाय, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, डिजिटल शिक्षण सुविधाओं और छात्र सहायता सेवाओं की कमी बनी हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा राज्य में पीएम-उषा समर्थित कॉलेजों में छात्रों के नामांकन, प्रतिधारण और रोजगार क्षमता के परिणामों में सुधार पर कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि पीएम-उषा वित्तपोषण तमिलनाडु के सभी जिलों में बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक समान पहुंच में परिवर्तित हो?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए विभिन्न

योजनाओं को कार्यान्वित किया है। एआईएसएचई रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में 34,04,989 छात्रों के नामांकन के साथ कुल 65 विश्वविद्यालय और 2913 कॉलेज हैं।

भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करके उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषण करना है। सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, रूसा के पहले चरण की प्रतिबद्ध देनदारियों सहित, जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) का तीसरा चरण शुरू किया है।

तमिलनाडु राज्य में, रुसा के तहत, अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न घटकों के तहत कुल 873.95 करोड़ रुपये की 100 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों, छात्रावासों, अनुसंधान सुविधाओं, डिजिटल प्रयोगशालाओं और उच्च शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक अन्य सक्षम सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल है। कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से 90 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान, अब तक राज्य को 60.91 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है

इस योजना के तहत, अगले चरण में पीएम-उषा को जारी रखने के लिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा अगस्त 2025 में एक तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया गया, जिसने योजना को जारी रखने की सिफारिश की। इस योजना को पीएम- उषा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2028 तक और रुसा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने (अर्थात 30 सितंबर, 2026) तक आगे बढ़ाया गया है।

*****